

प्रपत्र-23

परियोजना का नाम :-

तक बोर्ड

स्वतंत्रता लगाए लेनानियों के ग्राम चलाएँ

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम — बालामुक
तहसील — (१०२), जिला — (३५२) का

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद — (३०१) के अन्तर्गत — (३५२) का परियोजना के निर्माण हेतु (—) हे ० आरक्षित वन भूमि, (१५) हे ० सिविल सोयम भूमि (०.९८) हे ०, वन पंचायत भूमि (१.२१८) हे ०) अर्थात कुल (२.२८८) हे ० वन भूमि का (३०१) विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत (३०१) द्वारा दिनांक १३-१०-०८ को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।


चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम (३०१) के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

हे ०/-

ग्राम सचिव

नोट :- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रधान कमान
ग्राम चलाएँ हे ०/- धन्देलमाड
ग्राम प्रधान प्रधान संसाधन
दिकारां खण्ड - शहर (अल्पोड़ा)

प्रपत्र-23.1

13-10-2014

दिनांक को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत यलमाड़

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	सी इन्दुसिंह छिंड	<i>S. Indusinh Chind</i>
2-	शर्मा जगदरमिंद लिंद	<i>Sharma Jagadramind Lind</i>
3-	शर्मा आनन्दसिंह	<i>Sharma Anand Singh</i>
4-	कोटी गणेशचंद्र रायह	<i>Koti Ganeshchandar Rayha</i>
5-	कोटी चन्द्रमसिंह	<i>Koti Chandramsingh</i>
6-	कोटी घटिपालमिंद	<i>Koti Ghatipal Minsing</i>
7-	कोटी जनरामसिंह	<i>Koti Janaramsingh</i>
8-	कोटी देवेशसिंह	<i>Koti Devesh Singh</i>
9-	कोटी दीपालसिंह	<i>Koti Deepal Singh</i>
10	कोटी कलबलसिंह	<i>Koti Kalbal Singh</i>
11	कोटी महेशसिंह	<i>Koti Mahesh Singh</i>
12	कोटी कुल रामसिंह	<i>Koti Kul Ram Singh</i>
13	कोटी चंपालालसिंह	<i>Koti Champa Lal Singh</i>
14	कोटी नरायणसिंह	<i>Koti Narayan Singh</i>
15	कोटी भानासिंह	<i>Koti Bhana Singh</i>
16	कोटी गोपालसिंह	<i>Koti Gopal Singh</i>
17	कोटी उच्चरावासिंह	<i>Koti Uccharav Singh</i>
18	कोटी अमन-दास	<i>Koti Amn Das</i>
19	कोटी दिवेशसिंह	<i>Koti Divesh Singh</i>
20	कोटी च-दनसिंह	<i>Koti Ch-Dan Singh</i>
21	श्राविती वसन्ती देवी अलगुक्कर (पथान)	<i>Srawiti Vasanti Devi Algukkar (Pathan)</i>

प्रधान कमला

ग्राम पंचायत - थलमाड़

पौ. शो. देवायल

विकास खण्ड (अल्मोड़ा)

परियोजना का नाम :-

जनपद दल्लोड़े वे स्वतंत्र लग्जरी प्रोजेक्टों के जाते दल्लोड़े मोटर चारी का भव चिह्नित

बन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण - पत्र

ग्राम पंचायत का नाम - देवायल

तहसील सूरज जिला झालोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र दल्लोड़े परियोजना के निर्माण हेतु (.....)

उत्तराखण्ड में जनपद दल्लोड़े के अन्तर्गत दल्लोड़े हेतु आरक्षित बन भूमि ५१९८.७ हेतु सिविल सौयम भूमि १२१३ हेतु) अर्थात कुल २१२०५ हेतु बन भूमि का ५१९८.७ विभाग / संस्था के पक्ष ने भारत सरकार, पर्यावरण एवं बन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्त्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तूत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत देवायल द्वारा दिनांक 13-10-2014 के सम्बन्ध में ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित बन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि बन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रविधानों के तहत आवेदित बन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। लग्जरी सभी ग्रामवासियों द्वारा स्वच्छ किया गया कि उक्त बन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित बन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम देवायल के ग्रामवासियों को सक्त बन भूमि ५१९८.७ प्रयोगता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रधान
ग्राम पंचायत देवायल
विठ्ठल सल्ट (अल्मोड़ा)

Croct 16/10/2014
ग्राम पंचायत देवायल
ग्राम पर Malmaud
salt

ग्राम प्रधान / सरपंच
मुहर सहित

प्रारूप - 23.1

दिनांक 13-10-2014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत देवायल

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ की ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	जीवन मिश्र	जीवन
2	जगद्दा मिश्र	जगद्दा मिश्र
3	रामचंद्र मिश्र	रामचंद्र
4	भरत मिश्र	भरत मिश्र
5-	रुद्रालम्ब मिश्र	रुद्रालम्ब मिश्र
6	जीत मिश्र	जीत मिश्र
7	कुम्भेश राम	कुम्भेश

ग्राम पंचायत देवायल
विधायक सभा (अल्मोड़ा)

ग्राम प्रधान / सचिव

प्रपत्र-23.2

परियोजना का नाम :-

कार्यालय उप जिलाधिकारी, सलू
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत^{प्रमाण-पत्र}
उपखण्ड स्तरीय समिति, _____

उपर्युक्त परिक्षेत्र के अन्तर्गत स्वतंत्र दंगाम समिति के हो ५० आरक्षित वन भूमि, ५० सिविल एवं सोयम वन भूमि हो ५० वन पचायत भूमि, अर्थात् कुल हो वन भूमि) का प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपर्युक्त स्तरीय समिति, (तहसील सरकारी) की दिनांक १३-१०-०१६ को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री एम.एम. दास, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानसार है।

- | | | | |
|------|--|---------------|--------------|
| 1- | श्री <u>प्रभागीय राणा</u> उपजिलाधिकारी | <u>स०८</u> | अध्यक्ष |
| 2- | श्री <u>विजय कुमार विजय</u> उप प्रभागीय वनाधिकारी | <u>२५४८०८</u> | सदस्य |
| 3- | श्री <u>रमेश सहायक</u> सहायक समाज कल्याण अधिकारी | <u>A1</u> | सदस्य / सचिव |
| वायल | श्री <u>राधाराम</u> बी०डी०सी० क्षेत्र <u>द्वाराधाम</u> | | सदस्य |

रामपाल कुमार अल्पेश उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी Rampal की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि

परियोजना हेतु.....हे० वन

भूमि प्राचीन राज्यों का नाम है।

प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों
के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त
भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग
हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है। ११

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, ~~वन अधिकारी~~ द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

~~बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड~~ परिषेक्र के अन्तर्गत
हो वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर
प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील
जनपद
(Signature)
(Date)

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, अनंगना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील
जनपद
(Signature)
(Date)

(Signature)
Anup

(Signature)
काशिल लक्ष्मी बाबू
राष्ट्रवारी खोला तह
जनपद (राष्ट्रवारी)

प्रपत्र-23.4

परियोजना का नाम :-

स्वतंत्रता राज्य सेनानिपो के द्वारा लकड़ी का नवायिका।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद भूमि

के अन्तर्गत प्रस्तावित स्वतंत्रता राज्य के द्वारा लकड़ी का नवायिका।

एम. एफ. एस.

परियोजना के निर्माण हेतु २०२० में है, वन भूमि लोकोक्ता (प्रयोक्ता एजेन्सी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या 11-9/98-एफ0सी0 दिनांक 05-02-2013 के द्वारा रेखाकार (linear) प्रयोजनों यथा—सड़क, नहर, पारेषण लाईन, ओरेफ0सी0 केबिल व पाईपलाईन बिछाने आदि के प्रकरणों को वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों से मुक्त किया गया है। विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व आदिकालीन कृषि समुदाय (Pre Agricultural Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

जिला समाज कल्याण अधिकारी
लकड़ी

जिलाधिकारी

A meeting of the district level committee of Almora district, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr. Vinod Kumar Suman, I.A.S. Deputy Commissioner, Almora on date...16.01.15.....at time...6:00 PM.....at Almora, in which application claiming rights of area measuring 2.205 hect. for the Construction of Sudarshana Sangram village Thalmar..... of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Almora sub division were discussed to consider the same of admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above for diversion of land for the said purpose.

Place : Almora

Date :

जिला अधिकारी
अल्मोड़ा
Signature

(Full name of the official seal of the District Collector)

It is further certified that

S.N.		Remarks
(a)	The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out for the entire 2205' het. of forest area proposed for diversion/copy of records of all consultations and meetings of the forest Rights committee(s) and the District level Committee are enclosed annexure 1 to annexure.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers.
(b)	The diversion of forest land for Facilities managed by the Goverment as required under section 3(2) of the FRA have been Complete and the Gram Sabhas have given their consent to it.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers there is no objection certificate of concerned motor road is affixed in the forest file
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and preagricultural communities.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.

Encl:As above

(Full name of the official seal of the District Collector)


निल
16/01/2015
Signature

FORM-1
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector : Rudraprayag

No :.....

Dated:.....

TO WHOMSOEVERT IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forest(MoEF), Government of India's letter No:- 11-9/98-EC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers) Recognition of Forest Right, Act 2006(FRA, for Short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 23013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of liner projects. It is certified that 2.205....hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Rural Development Dept. Uttarakhand (Name of user agency) for Construction of Sutnistha Sangram Senani village Thalmar Road.....(Purpose for diversion of forest land) in Almora....district falls within jurisdiction of Thalmar.....village(s) in Salt.....Tehsils.

It is further Certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 2.205 Hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the forest Rights Committee(s), Gram sabha(s), Sub-Division Level committee(s) and District Level Committee are enclosed as annexure I to-annexure.
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) to the FRA have completed and the Gram sabhas given their consent of it.
- (c) The proposal dose not involve recognized of primitive Trible Groups and pre-agricultural communities.

Encl:As above


निला अधिकारी
Signature


(Full name of the official seal of the District Collector)